



माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र

प्रलम्बिस् के लयिः

माइक्रोफाइनेंस, हाशरि पर पड़े समूह, महिला सशक्तीकरण, माइक्रो फाइनेंस संसथान (MFI), स्वयं सहायता समूह (SHG), गरीबी उनमूलन, भारतीय रज़िरव बैंक (RBI), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, भारतीय माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड (IMEF), ई-शक्तीपिहल, कषेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), सहकारी समतियिँ ।

मेन्स के लयिः

वत्तीय समावेशन में माइक्रोफाइनेंस कषेत् की भूमकि ।

माइक्रोफाइनेंस कषेत् वत्तीय समावेशन का एक महत्त्वपूरण घटक है, जो वंचति आबादी को छोटे-छोटे ऋण, बचत, बीमा और अन्य सेवाएँ प्रदान करता है । यह वकिसशील अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी उनमूलन, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में एक परविरत्नकारी भूमकि नभिता है ।

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

परचियः

- **माइक्रोफाइनेंस** से तात्पर्य उन परिवारों, छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को छोटे मूल्य के ऋण सहति वत्तीय सेवाएँ प्रदान करना है, जनिकी औपचारकि बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं है ।
- यह **वत्तीय समावेशन** के लयि एक प्रभावी साधन है, जो हाशरि पर पड़े और नमिन आय वर्ग, वशिषकर महिलाओं को सामाजकि समानता और सशक्तीकरण प्राप्त करने में सकषम बनाता है ।
- भारत में माइक्रोफाइनेंस कषेत् में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा 29 राज्यों, 4 केंद्रशासति प्रदेशों और 563 ज़िलों में 168 माइक्रो फाइनेंस संसथान (Micro Finance Institutions- MFI) कार्यरत हैं ।
- ये MFI 46,842 करोड़ रुपए के बकाया ऋण पोर्टफोलियो के साथ 3 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं ।
- भारत में माइक्रोफाइनेंस कषेत् का वकिसः भारत में माइक्रोफाइनेंस कषेत् का वकिस चार मुख्य चरणों में हुआः

प्रारंभकि काल (1974-1984):

- 1974: असंगठति कषेत् की महिलाओं को वत्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लयि श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना की गई ।
- 1984: नाबारड ने गरीबी उनमूलन के लयि एक उपकरण के रूप में **स्वयं सहायता समूह (Self Help Group- SHG)** को जोड़ने की समर्थन की ।

परविरत्न अवधि(2002-2006):

- 2002: स्वयं सहायता समूहों को असुरकषति ऋण देने के मानदंडों को अन्य सुरकषति ऋणों के अनुरूप कर दिया गया ।
- 2004: भारतीय रज़िरव बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस को प्राथमकिता कषेत् में शामिल कयि तथा MFI को वत्तीय समावेशन के साधन के रूप में मान्यता दी ।
- 2006: उच्च ब्याज दरों और अनैतकि वसूली प्रथाओं के आरोपों के कारण सरकार को कुछ MFI की शाखाओं को बंद करना पड़ा ।

वकिस और संकट (2007-2010):

- 2007: नज्ी इक्विटी अभकिर्त्ताओं ने बाज़ार में प्रवेश कयि, जसिसे MFI ऋण पुस्तकि (35 बलियिन रुपए) में तेज़ी से वृद्धि हुई ।
- 2009: माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (Microfinance Institutions Network- MFIN) का गठन कयि गया, जसिसे NBFC-MFI को सदस्य बनने की अनुमति मिली ।
- 2010: आंध्र प्रदेश में संकट सामने आया, जसिमें जबरन ऋण वसूली की प्रथाएँ शामिल थीं, जसिके कारण उधारकर्त्ताओं ने आत्महत्या कर ली ।

सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसने MFI गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगाया।

समेकन और परपिक्वता (2012-2015):

- **2012:** मालेगाम समिति ने परिवर्तन की सफारिश की और आरबीआई ने नए नियम लागू किये।
- **2014:** RBI ने सबसे बड़े माइक्रोफाइनेंस बंधन बैंक को **यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस** जारी किया। MFIs को **स्व-नियामक संगठन (SRO)** के रूप में मान्यता दी गई।
- **2015:** सरकार ने छोटे व्यवसायों को वित्तपोषण करने के लिये **मुद्रा बैंक की शुरुआत** की।

भारत में माइक्रोफाइनेंस की स्थिति:

- **राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (National Council of Applied Economic Research- NCAER)** के एक अध्ययन के अनुसार, माइक्रोफाइनेंस लगभग **130 लाख नौकरियों और हमारे GVA में 2%** का योगदान देता है।
- इसमें **सभी 6.3 करोड़ असंगठित और गैर-कृषि उद्यमों** तक पहुँचने की क्षमता है। RBI ने हाल ही में माइक्रोफाइनेंस को 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को दिये जाने वाले संपार्ष्वकि-मुक्त ऋण के रूप में परभाषित किया है।

माइक्रोफाइनेंस में व्यवसाय मॉडल:

- **स्वयं सहायता समूह (SHG):**
 - SHG 10-20 सदस्यों के अनौपचारिक समूह हैं, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएँ शामिल हैं, जो अपनी बचत को एकत्रित करते हैं और SHG-बैंक लिकेज प्रोग्राम (SHG-BLP) के तहत औपचारिक बैंकिंग संस्थानों से ऋण के लिये पात्र बन जाते हैं। नाबारड SHG के विकास और समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI):**
 - MFI सूक्ष्म ऋण और बचत, बीमा और धन प्रेषण जैसी अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। ऋण आमतौर पर संयुक्त ऋण समूहों (Joint Lending Groups- JLG) के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं, जो समान आर्थिक गतिविधियों में लगे 4-10 सदस्यों के अनौपचारिक समूह होते हैं जो संयुक्त रूप से ऋण चुकाते हैं।
- **माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं की श्रेणियाँ:**
 - **गैर-सरकारी संगठन (NGO-MFI):** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1880 के तहत पंजीकृत ये NGO सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं।
 - **सहकारी समितियाँ: प्रासंगिक कानूनों के तहत पंजीकृत, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (Primary Agricultural Credit Societies- PACS)** जैसी सहकारी समितियाँ सूक्ष्म वित्त सेवाएँ प्रदान करती हैं।
 - **धारा 8 कंपनियाँ (पूर्व में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25):** ये गैर-लाभकारी संस्थाएँ हैं जो **कंपनी अधिनियम, 2013** के अंतर्गत सूक्ष्म ऋण प्रदान करती हैं।
 - **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-MFI):** NBFC-MFI अपने स्वयं के संसाधनों से या बैंकों से थोक ऋण लेकर JLG को ऋण देते हैं। RBI द्वारा वर्ष 2011 में शुरू की गई इस श्रेणी में माइक्रोफाइनेंस बाजार का 80% हिस्सा है।
- **नियामक ढाँचा:**
 - भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) 01.07.2014 को जारी **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (NBFC-MFI) ढाँचे** के माध्यम से भारत में MFI को वनियमित करता है।
 - दशान्तरिक्षों में **पंजीकरण के लिये पात्रता, ग्राहक सुरक्षा**, उधारकर्ताओं के अति-ऋणग्रस्तता की रोकथाम, गोपनीयता और ऋण का मूल्य निर्धारण जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। MFI आमतौर पर इन वनियमों का अनुपालन करते हैं, जिससे क्षेत्र में हितधारकों का विश्वास बढ़ता है।

माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (MFI) के विकास के लिये सरकार के क्या उपाय हैं?

- **भारतीय सूक्ष्म वित्त इक्विटी फंड (IMEF):** तरलता चुनौतियों से निपटने के लिये, भारत सरकार ने 2011-12 के केंद्रीय बजट में **100 करोड़ रुपए** के प्रारंभिक आवंटन के साथ **भारतीय सूक्ष्म वित्त इक्विटी फंड (Indian Micro Finance Equity Fund- IMEF)** की शुरुआत की।
 - **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** के माध्यम से संचालित इस कोष का उद्देश्य, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, छोटे, सामाजिक रूप से अनुमुख MFI के पंजीकरण को मजबूत करना था।
- **नाबारड की भूमिका:** नाबारड का माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन विभाग विभिन्न माइक्रोफाइनेंस नवाचारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित गरीबों के लिये वित्तीय सेवाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।
- **स्वयं सहायता समूह-बैंक लिकेज कार्यक्रम (SHG-BLP):** SHG-BLP गरीब परिवारों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से जोड़ने वाला एक लागत प्रभावी मॉडल है।
- **नाबारड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (NABFINS):** नाबारड ने NABFINS की स्थापना एक आदर्श माइक्रोफाइनेंस संस्थान के रूप में की, जिसका ध्यान शासन, पारदर्शिता और उचित ब्याज दरों पर केंद्रित था।
- **सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDP):** उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाने के लिये स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिये कौशल प्रशिक्षण।
- **ई-शक्ति पहल:** नाबारड द्वारा शुरू की गई **ई-शक्ति पहल** माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के लिये एक प्रमुख तकनीकी प्रगति है। यह परियोजना मौजूदा स्वयं सहायता समूहों (SHG) की मैपिंग और एक समर्पित वेबसाइट पर वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह की जानकारी अपलोड करने पर केंद्रित

है।

○ स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण से **पारदर्शिता** में सुधार होता है, डेटा तक बेहतर पहुँच संभव होती है तथा वित्तीय समावेशन प्रयासों में अधिक दक्षता आती है।

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): वर्ष 2015** में शुरू की गई **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** को छोटे व्यवसायों के लिये ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु शुरू किया गया था, जो वित्तीय समावेशन का एक आवश्यक घटक है।

माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेशन में किस प्रकार योगदान देता है?

- हाल के वर्षों में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद, इसमें आगे वृद्धि और विकास के अनेक अवसर हैं।
- **गरीबी उन्मूलन: माइक्रोफाइनेंस** नमिन आय वाले व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके **गरीबी उन्मूलन** के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- अध्ययनों से पता चला है कि माइक्रोफाइनेंस **लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर सकता है**, जिससे वे अपने आय स्रोतों में विविधता ला सकते हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं।
- **स्वास्थ्य, सामाजिक पूंजी और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** माइक्रोफाइनेंस का स्वास्थ्य और शिक्षा सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो बाद में आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।
- **उदाहरण के लिये, ग्रामीण बैंक** द्वारा किये गए शोध से पता चलता है कि माताओं को ऋण तक पहुँच प्रदान करने से उनके **बच्चों की स्कूल नामांकन दर लड़कियों के लिये लगभग 1.9% और लड़कों के लिये 2.4% बढ़ सकती है।**
- **विकास उपकरण के रूप में माइक्रोफाइनेंस:** माइक्रोफाइनेंस अप्रत्याशित संकटों, जैसे कि व्यावसायिक जोखिम या आपूर्ति में व्यवधान, के विरुद्ध एक बफर के रूप में कार्य कर सकता है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि माइक्रोफाइनेंस **राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव** के प्रति अपेक्षाकृत लचीला है तथा कठिन समय के दौरान एक विश्वसनीय सहायता प्रणाली प्रदान करता है।
- **वाणज्यिक बैंकों के लिये अवसर: चूंकि अनेक माइक्रोफाइनेंस संस्थान सीमिति रेंज में माइक्रोफाइनेंस उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, इसलिये वाणज्यिक बैंकों के लिये इस क्षेत्र में नवीन पेशकश** विकसित करने का अवसर है।
- शोध से पता चलता है कि माइक्रोफाइनेंस उत्पादों की वसूली दर और लाभप्रदता उच्च हो सकती है।
- **महिला सशक्तीकरण: माइक्रोफाइनेंस महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।**
- कई लघु वित्त संस्थाएँ, विशेषकर **बांग्लादेश जैसे देशों में**, महिलाओं को ऋण देने को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि उनकी पुनर्भुगतान दर अधिक होती है।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा क्या है?

परिचय:

- **वित्तीय समावेशन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, " कमजोर वर्गों और नमिन आय वर्ग जैसे संवेदनशील समूहों को, जहाँ आवश्यक हो, वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं और समय पर पर्याप्त ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।"**

नमिन आय वाले परिवारों के लिये चुनौतियाँ:

- नमिन आय वाले परिवारों के पास अक्सर बैंक खाते तक पहुँच नहीं होती और उन्हें नमिन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है:
 - बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिये **कई बार चक्कर लगाने** पर समय और पैसा खर्च करना
 - **बचत खाता** खोलने या ऋण प्राप्त करने में कठिनाई
 - परिणामस्वरूप, **बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी** बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रणाली से कट गई है।

वित्तीय बहिष्करण:

- **उन्नत ग्राहक विभाजन प्रौद्योगिकी** जैसी कुछ प्रवृत्तियों ने विशिष्ट समूहों के लिये वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया है।
 - इससे एक विभाजन पैदा होता है, जहाँ उच्च और उच्च-मध्यम आय वर्ग की आबादी को व्यक्तिगत वित्त विकल्पों की एक विस्तृत शृंखला का लाभ मिलता है, जबकि एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के पास बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक भी पहुँच नहीं है। इस पहुँच की कमी को **"वित्तीय बहिष्कार"** कहा जाता है।

वित्तीय समावेशन में पारंपरिक मॉडल की विफलता:

- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB): 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों** की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी तक औपचारिक ऋण प्रणाली का विस्तार करना था।
- **RRB अधिनियम, 1976 में** ग्रामीण क्षेत्र को पर्याप्त और समय पर वित्त उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता के कारण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को **गैर-निष्पादित आसतियों (Non-Performing Assets- NPA)** और परिचालन लागत के उच्च स्तर से जूझना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप भारी घाटा हुआ है।
- **सहकारिता: ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की** स्थापना छोटे साधन वाले लोगों के संसाधनों को एकत्रित करने तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिये की गई थी।

- हालाँकि देशकों के सहकारी प्रयासों के बावजूद, नजी एजेंसियों का ग्रामीण ऋण बाज़ार पर प्रभुत्व बना रहा और सहकारी समितियों किसानों की कुल उधारी ज़रूरतों का केवल 35% ही पूरा कर सकीं।

भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के लिये चुनौतियाँ और आगे की राह क्या हैं?

चुनौती	आगे की राह
दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च आउटरीच लागत।	प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, स्थानीय व्यवसायों के साथ साझेदारी करना, क्षेत्र बल का अनुकूलन करना।
उचित मूल्यांकन के अभाव के कारण अत्यधिक ऋणग्रस्तता।	जोखिम मूल्यांकन को मज़बूत करना, वित्तीय शिक्षा प्रदान करना, ऋण उत्पादों में विविधता लाना।
मुख्यधारा के बैंकों की तुलना में प्रतिसिपर्द्धात्मक नुकसान।	वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों की खोज करना, मूल्य-वर्द्धति सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना, नियामक सुधारों का समर्थन करना।
मूल्यांकन के लिये विश्वसनीय डेटा प्राप्त करने में कठिनाई।	मानकीकृत मूल्यांकन ढाँचे का विकास करना, डेटा विश्लेषण में नविश करना, बाहरी सत्यापन की कोशिश करना।
शहरी गरीबों तक सीमिति पहुँच।	उत्पादों और सेवाओं को अनुकूलित करना, शहरी स्थानीय नकियाँ के साथ साझेदारी करना, डिजिटल चैनलों का लाभ उठाना।
अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन पद्धतियाँ और संपार्श्विक का अभाव।	ऋण जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, संपार्श्विक आवश्यकताओं पर विचार करना।
खराब बुनयिदी ढाँचे के कारण दूरदराज के क्षेत्रों में ग्राहकों तक पहुँचने में कठिनाई।	मोबाइल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, स्थानीय एजेंटों के साथ साझेदारी करना, बुनयिदी ढाँचे में नविश करना।
सीमिति परिचालन लचीलापन और बैंकगि नीतियों में उतार-चढ़ाव के प्रती संवेदनशीलता।	वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों की खोज करना, आंतरिक क्षमता का निर्माण करना, नीतगित परिवर्तनों का समर्थन करना।
वित्तीय सदिधांतों और सेवाओं के बारे में जागरूकता का अभाव।	वित्तीय साक्षरता अभियान चलाना, स्कूलों और कॉलेजों के साथ साझेदारी करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना।

नषिकर्ष

माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने एक व्यवसाय मॉडल के रूप में अपनी व्यवहार्यता साबति की है और साथ ही गरीब, हाशिए पर पड़े लोगों और बैंकगि सेवाओं से वंचित लोगों सहति आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हसिसे तक पहुँचने की अपनी क्षमता भी साबति की है। बैंकगि प्रणाली के पूरक के रूप में कार्य करते हुए इसने वंचितों को स्थायी माइक्रोफाइनेंस सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास कथि है, जसिसे देश में अधिक समावेशी विकास और आर्थिक समानता प्रदान की जा सके।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

Q. माइक्रोफाइनेंस कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें उपभोक्ता और स्वरोज़गार करने वाले दोनों शामिल हैं। माइक्रोफाइनेंस के तहत दी जाने वाली सेवा/सेवाएँ हैं (2011)

1. ऋण सुवधिएँ
2. बचत सुवधिएँ
3. बीमा सुवधिएँ
4. फंड ट्रांसफर सुवधिएँ

सूचियों के नीचे दथि गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनथि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

